



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

शनिवार, 23 जनवरी, 2016 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत्त के अंश

मद संख्या 56/2016

संकल्प संख्या 36/2016

बी सी आई : डी : सं. 1731/2016.—माननीय सदस्यों ने राज्य विधिज्ञ परिषदों के पदाधिकारियों के विरुद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों के भिन्न-भिन्न नियमों का मुद्दा उठाया और कहा कि इन नियमों में कोई एकरूपता नहीं है।

कुछ राज्य विधिज्ञ परिषद् में अपने पदाधिकारियों के खिलाफ "अविश्वास प्रस्ताव" लाने के लिए कोई नियम नहीं है।

विधिज्ञ परिषदों में बढ़ते गुटबाजी के कारण, कई अवसरों पर इस परिषद् को शिकायतें प्राप्त होती रही हैं और कई समय एक बहुत ही विषम परिस्थिती पैदा होती है, कुछ राज्य के कुछ अव्यवाहारीक नियमों के कारण कुछ राज्य विधिज्ञ परिषदों की परिस्थिती में अवांछित गुटबंदी, जिसके बढ़ने के परिणामस्वरूप अस्वास्थ्यकर वातावरण और विधिज्ञ परिषदों के काम काज में अकुशलता रहती है। माननीय सदस्यों ने एकरूपता उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् में उनके पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से सम्बंधित एक नियम बनाने की आवश्यकता महसूस की है। विस्तृत विचार करने के बाद और नियम समिति से राय आमंत्रित करने के पश्चात, परिषद् ने सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों में उनके पदाधिकारियों के विरुद्ध पारित "अविश्वास प्रस्ताव" से सम्बंधित नियम संकल्पीत करते हुए निम्नलिखित एक समान दिशा निर्देश पारित कर रही है। ये दिशा निर्देश अनिवार्य प्रकृति का होगा और राज्य विधिज्ञ परिषदों को अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है और/या इन नियमों या संकल्प के अनुपालन में, सेवा बनाए/अपने नियम का संशोधन करे।

1. "अविश्वास प्रस्ताव" राज्य विधिज्ञ परिषद् के केवल किसी पदाधिकारी के खिलाफ ही पारित किया जा सकता है/या लाया जा सकता है।

2. राज्य विधिज्ञ परिषद् अपने किसी भी सदस्य के विरुद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" नहीं ला सकता है।

3. राज्य विधिज्ञ परिषद् भारतीय विधिज्ञ परिषद् में उनके सदस्य प्रतिनिधि के खिलाफ कोई "अविश्वास प्रस्ताव" पारित नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर राज्य विधिज्ञ परिषद् के तीन चौथाई सदस्यों को किसी साबित कदाचार या भारतीय विधिज्ञ परिषद् का सदस्य जो राज्य विधिज्ञ परिषद् में किसी एक अपराध के विषय में नैतिक अधमता का दोषी पाया जाता है और 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास की सजाआफता है तो राज्य विधिज्ञ परिषद् के तीन चौथाई सदस्य इस तथ्य को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संज्ञान में लाने के लिए एक संकल्प पारित कर सकते हैं और तब भारतीय विधिज्ञ परिषद् इसके सम्बंध में अपने सम्बंधित नियम "अविश्वास प्रस्ताव विरुद्ध पदाधिकारी एवं सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम 2015" के अनुसार कार्य करेगा।

4. भारतीय विधिज्ञ परिषद् किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरुद्ध “अविश्वास प्रस्ताव” और परिषद् के दो तिहाई सदस्यों द्वारा जिसमें अनिवार्य रूप से पदेन सदस्य भी शामिल होंगे के हस्ताक्षरित प्रार्थना पर “अविश्वास प्रस्ताव” ले सकता है और पारित कर सकता है और “अविश्वास प्रस्ताव” पारित होने के लिए परिषद् के कम से कम तिन चौथाई सदस्यों, जिसमें एक पदेन सदस्य भी शामिल हो के द्वारा “अविश्वास प्रस्ताव” के पक्ष में मतदान करने की आवश्यकता होगी।

5. राज्य विधिज्ञ परिषद् में उनके पदाधिकारियों के विरुद्ध “अविश्वास प्रस्ताव” लाने और पारित करने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए एक प्रार्थना पर सम्बंधित परिषद् के कम से कम दो तिहाई सदस्य, जिसमें अनिवार्य रूप से पदेन सदस्य शामिल हो, द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। “अविश्वास प्रस्ताव” के पारित होने के सम्बंध में, सम्बंधित परिषद् के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों को “अविश्वास प्रस्ताव” में भाग लेना और “अविश्वास प्रस्ताव” के पक्ष में मतदान करना अनिवार्य होगा। पदेन सदस्य को भी बैठक में भाग लेना चाहिए और मांग पारित तभी किया जा सकेगा यदि पदेन सदस्य “अविश्वास प्रस्ताव” के पक्ष में मतदान करे।

6. सम्बंधित पदाधिकारी या सदस्य को जिसके विरुद्ध इस तरह का “अविश्वास प्रस्ताव” लाने का प्रस्ताव है को कम से कम 30 दिनों का सूचना दिये जाने की आवश्यकता है और “अविश्वास प्रस्ताव” लाने के लिए यह बैठक, सम्बंधित परिषद् के सचिव के द्वारा प्रार्थना प्राप्त करने के कम से कम 45 दिनों के उपरान्त आयोजित कि जा सकती हैं

7. “अविश्वास प्रस्ताव” पारित करने के प्रार्थना के लिए आवश्यक होगा कि कारणों और आधार जिसके आधार पर इस “अविश्वास प्रस्ताव” को ले आने का प्रस्ताव है निर्दिष्ट वं सामिल हो सम्बंधित सदस्य/पदाधिकारी को “अविश्वास प्रस्ताव” दिये जाने के प्रस्ताव की मांग के साथ कारण और आधार अस्पष्ट, गैरविशिष्ट, व्यक्तिगत प्रतिशोध पर नहीं होना चाहिए और दस्तावेज के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। मांग के असलियत और प्रामाणिकता की जाँच, जिस पदाधिकारी के खिलाफ “अविश्वास प्रस्ताव” पारित होना है को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद करना होगा।

राज्य विधिज्ञ परिषद् से सम्बंधित यह जाँच, एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होंगे (i) किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश/किसी भी उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश जिसकी न्यूनतम सात साल का अनुभव हो जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा मनोनित किया जाएगा (ii) एक वरिष्ठ अधिवक्ता जिसका अधिवक्ता के रोल पर कम से कम 35 साल का अभ्यास हो, का चैनन सम्बंधित परिषद् के सामान्य सभा द्वारा कि गई हो (iii) एक अच्छी ख्याति का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिसका न्यूनतम 35 साल का अभ्यास हो, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के द्वारा भिन्न राज्य से जहाँ “अविश्वास प्रस्ताव” लाया गया है, नामित होगा।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् से सम्बंधित जाँच, “भारतीय विधिज्ञ परिषद् लोक शिकायत निवारण” द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(यह समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व माननीय न्यायाधीश जो कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित हो द्वारा किया जाएगा और जिसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश भी शामिल होंगे)

ऐसी समिति की रिपोर्ट को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सामान्य सभा के समक्ष “अविश्वास प्रस्ताव” पर विचार के पूर्व रखा जाना आवश्यक है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पिछले संकल्प दिनांक 26.06.2013 पारित तहत मद् संख्या 69/2013, 2015 के संकल्प संख्या 264 अब तक कि जो कि “अविश्वास प्रस्ताव” से सम्बंधित है और अन्य सभी संकल्प सिरे से निरस्त हो गया और/या तदनुसार संशोधित हो गया। भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निर्णय दिनांक 18.10.2015 जो कि अन्य सभी बैठकों (अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर) के लिए कोरम संकल्प संख्या 264/2015 के अनुसार बरकरार रहेगा।

“अविश्वास प्रस्ताव” एक बार में विफल हो जाता है, तो अगले 12 महीने तक उसी पदाधिकारी/सदस्य के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। यह नियम भारतीय विधिज्ञ परिषद् और सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् दोनों पर लागू होगा।

राज्य विधिज्ञ परिषदों को निर्देशित किया जाता है कि नियम में एकरूपता के लिए उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए नियम को बनाए या संशोधित करे और इसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 के धारा 28 (3) के तहत आवश्यक मंजूरी के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेजे।

कार्यालय इस दिशा निर्देश और संकल्प को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन कराने के लिए तत्काल कदम उठाए।

अतिविशिष्ट रूप से, इस प्रस्ताव को किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरुद्ध साबित कदाचार के मामलों में ही लाया जा सकता है या यदि वह नैतिक अधमता के कुछ अपराध का दोषी पाया गया है और कम से कम दो साल के लिए कारावास से गुजरने के लिए सजा सुनाई गई है।

ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अशोक कुमार पाण्डेय, सयुक्त सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 36(96)]

BAR COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2016

Extract of the minutes of meeting of the General Council of the Bar Council of India which was held on Saturday, 23rd January, 2016.

Item No. 56/2016**Resolution No. 36 /2016**

BCI : D : No. 1731/2016.—The Hon'ble Member have raised the issue of different types of rules with regard to "No Confidence Motion" against the office bearers of State Bar Councils in different State Bar Councils and have said that there is no uniformity in these rules.

Some of the State Bar Councils have no rule for bringing "No Confidence Motion" against their office bearers.

Due to increased groupism in the Bar Councils, on many occasions this Council has been receiving complaints and a very anomalous situation arises some times. Because of some impractical rule of some states, the situation in some of the State Bar Council leads to unwanted groupism, resulting in unhealthy atmosphere and inefficient functioning of the State Bar Councils. The Hon'ble Members have felt the need to frame a rule providing for uniformity in all the State Bar Councils as regards passing of No Confidence Motion against their office bearers. After thorough consideration and after inviting the opinion the Rules Committee, the Council is passing the following resolution laying down the uniform guidelines for all the State Bar Councils with respect to passing of a No- Confidence Motion against their office bearers. These guidelines are mandatory would in nature and the State Bar Councils are directed to follow and / or to frame service / amend their Rules in compliance of these Rules / Resolution.

1. No Confidence Motion can be passed/moved only against an office bearer in the State Bar Council.
2. State Bar Councils cannot bring a "No Confidence Motion" against any of its Member.
3. The State Bar Council cannot pass any "No Confidence Motion" against its Member representative in Bar Council of India. However, if the 3/4th Members of State Bar Council have some grievance of any proved misconduct or the Member, Bar Council of India from that State Bar Council is found guilty of an offence concerning moral turpitude and is convicted and sentence to undergo imprisonment for a period of 2 years or more, then the 3/4th Members of State Bar Council can pass a resolution to bring that fact to the notice of Bar Council of India and then the Bar Council of India shall act as per its Rule with regard to "No Confidence Motion" against the office-bearers and members of Bar Council of India Rule, 2015".
4. The Bar Council of India can move "No Confidence Motion" as against any Member or Office Bearers by taking up and passing a "No Confidence Motion" by moving a requisition which is to be signed by at least 2/3rd Members of the Council, which must include the ex-officio member. And with regards to the "No Confidence Motion" to be passed, at least 3/4th of Members of the Council shall required to vote in favour of the "No Confidence Motion" including at least one of the Ex-officio Member.
5. A requisition for holding meeting of the State Bar Council for taking up and passing a "No Confidence Motion" against its Office Bearers has to be signed by at least 2/3rd members of the concerned Council, which must include the ex-officio Member. With regards to the "No Confidence Motion" to be passed, at least 3/4th Members of the concerned Council shall be required to participate and vote in favour of "No Confidence Motion". The ex-officio Member should also participate in the meeting and requisition could be passed only if the ex-officio member votes in favour of "No Confidence Motion".
6. A notice of at least 30 days shall be required to be given to the concerned Office bearer or member against whom such "No Confidence Motion" is proposed to be moved & this meeting for taking up "No Confidence Motion" shall be held not less than 45 days after the requisition is received by Secretary of the concerned Council.
7. The requisition for passing of "No Confidence Motion" shall be required to contain and specify the reasons & grounds on the basis of which this "No Confidence Motion" is proposed to be moved. The reasons and grounds should not be vague, non specific, on personal vendetta and shall be required to be supported by materials along with the requisition of the motion of No Confidence is given to the concerned member/Office Bearer. An enquiry into the genuineness and bone-fide of the requisition has to be held, giving a reasonable opportunity of being heard to the office bearers against whom the "No Confidence Motion" is to be taken up.

This enquiry with regard to State Bar Council, shall be conducted by an independent body comprising (i) A former chief Justice of any High Court/a former Judge of any High Court having minimum experience of seven years as a Judge who will be nominated by the Chairman, Bar Council of India; (ii) A Senior Advocate having been on the roll of advocate for at least 35 years of practice chosen by the General Body of the concerned Council; and (iii) a senior Advocate of good repute & having minimum 35 years of practice to be nominated by Bar Council of India from a different State than the one where “No Confidence Motion” is moved.

The enquiry with regards to Bar Council of India, shall be conducted by the “Bar Council of India Public Grievance Redressal”.

(The said Committee is chaired by a former Hon’ble Judge of Supreme Court who is nominated by Hon’ble Chief Justice of India and also consists of Hon’ble Sitting Judges of High Courts.)

The report of such committee is required to be placed before the General House of the Bar Council of India on or before the “No Confidence Motion” is taken up.

The previous resolutions of the Bar Council of India dated 26.06.2013 passed under Item No.69/2013, Resolution No.264 of 2015 so far it relates to No Confidence Motion and all other resolution stand repealed and/or modified accordingly. The decision of Bar Council of India dated 18.10.2015 so far as quorum for all other meetings (except for a No Confidence Motion) shall be intact as per Resolution No.264/2015.

The ‘No Confidence Motion’ once failed cannot be brought against the same Office-Bearer/Member for the next 12 months. The Rules shall apply for all the State Bar Council and Bar Council of India both.

The State Bar Councils are directed to frame or amend their rules relating to passing of “No Confidence Motion” against Office Bearers so that they are in uniformity with the above guidelines and the same will be sent to Bar Council of India for its approval as required under Section 28(3) of the Advocates Act, 1961.

The Office is to take immediate steps for publishing these guidelines & this resolution in the Official Gazette.

More specifically, the motion can be brought only in case of proved misconduct of any member or office bearer or if he has been found guilty of some offence involving moral turpitude and has been sentenced to undergo imprisonment for at least 2 years.

These Rules will come in to force with immediate effect.

ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

[ADVT-III/4/Exty./36(96)]